Power shortage in Rajasthan

1433. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Central Electricity Authority, Rajashan State is likely to face power shortage of over 40 per cent by the end of the Eighth Five Year Plan;

(b) if so, whether any new power generation schemes have been proposed by Government of Rajasthan to augment the power supply position in the State;

(c) if so, what are the details thereof stating the decision, if any, by Central Government in this regard; and

(d) whether any special package is proposed to be initiated by Government to meet the current power shortage in Rajasthan?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) According to the 13th Electric Power Survey of India, Rajasthan is likely to face a peaking deficit of about 41 per cent and energy deficit of about 35 per cent at the end of the Eighth Plan period.

(b) and (c) The present status of the proposals received in the Central Electricity Authority (CEA) from the State Government for setting up of power projects in Rajasthan is given below:-

S.No.	Name (Thermal/Hydro)	Capacity (MW)	Present Status
1	Jawai Mini (H)	4×0.6	Reply from State Govt. is awaited on certain comments by the CEA.
2	Kota Pumped Storage (H) . . .	2×100	Reply of State Govt is awaited on certain comments by the CEA.
3	Suratgarh (T)	2×210	Coal linkage is yet to be tied up.
4	Dhaulpur (T)	2×210	Ministry of Environment and Forests have rejected the Project site as it was likely to have adverse effect on environment and on the Taj Mahal. Project authorities have to locate alternative site and submit a revised report.
5	Chittorgarh (T)	2×210	Further investigations are to be carried out by project authorities to tie up water and other inputs.
6	Mandalgarh (T)	3×210	
7	Rahughat (H)	4×40	Inter-state aspects need to be resolved.
8	Jakham (H)	1×5.5	Being a multipurpose project the scheme would first be required to be cleared by Technical Advisory Committee of the Ministry of Water Resources. Replies on certain comments of CEA are awaited.

(d) Measures for improving supply position include expediting the completion of ongoing projects, renovation and modernisation of existing power stations, reduction in transmission and distribution losses, efficient load management and energy conservation.

कोयला-उत्पादन के बढ़ाकर दर्शाये गए आंकड़े

1434. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० ने कोयला उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर दर्शाये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोल इंडिया लि० के निर्देशक के निर्देश से भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोल्ड फील्ड लि० द्वारा कोयला उत्पादन के आंकड़े बढ़ाकर दर्शाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार बढ़े आंकड़े दर्शाये जाने के बारे में जांच करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति कार्रवाई करने का भी विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयला कंपनियों के पास प्रतिमाह प्रत्येक खान द्वारा उत्पादित किए गए कोयले के भूमिगत भंडारों को नापने के लिए एक वैल्यूमेट्रिक प्रणाली है। इस आशय की प्रमाणिकता समय-समय पर कोल इंडिया लि० तथा सहायक कोयला कंपनियों के कारपोरेट कार्यालयों द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण दलों द्वारा की जाती है। अतः इस संबंध में उत्पादन की गलत सूचना प्रस्तुत करने की बहुत कम संभावना है, किन्तु किसी वस्तु की वास्तविक नापतोल की तुलना में वैल्यूमैट्रिक प्रणाली से की गई नाप में सदैव कुछ अंतर रह जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदाता समिति की हुई 30 जून 1988 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति गठित की जोकि निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ कोयले की उठाई गिरी, चोरी तथा कोयले के भंडारों की कमी के संबंध में आरोपित शिकायतों को जांच करेगी :-

(1) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की कोयले की सूचियों तथा उस की भंडारण नीति की जांच, और

(2) कोल इंडिया लि० द्वारा स्थापित की गई कोलियरियों/स्टाकयार्डों से कोयले का प्रेषण तथा प्राप्ति की जांच ।

इस संबंध में गठित उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बी०सी०सी०एल० में कोयला-उत्पादन

1435. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी०सी०सी० एल० का प्रबंधमंडल अपने प्रतिवेदनों और समाचार पत्रों में कोयला उत्पादन संबंधी आंकड़े हमेशा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करता है ;

(ख) क्या सरकार इन मिथ्या आंकड़ों की एजेंसी जांच कराने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या ऐसा दिल्ली में सहकारी अधिकारियों की मिली भगत से किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं । अन्य कोयला कंपनियों की तरह भारत कोकिंग कोल लि० में भी प्रतिमाह प्रत्येक खान द्वारा किए गए कोयले के उत्पादन के भी विगत भंडारों को नापने के लिए एक वैल्यूमेट्रिक प्रणाली विद्यमान है । कोयले का उत्पादन तथा उसके भंडारों के कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के मुख्यालय द्वारा नियुक्त किए गए सर्वेक्षण दल समय-समय पर अधिप्रमाणित करते हैं । अतः इस संबंध में उत्पादन के आंकड़ों को गलत प्रस्तुत करने की बहुत कम संभावना है।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० के बारे में विशेष रूप से कोई जांच किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। किन्तु संसदीय कार्य मंत्रालय की 30 अगस्त 1988 की अधिसूचना संख्या एफ० 8-7 ( ) /88-सी० बी० के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति गठित